भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2368

12.03.2026 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की प्रगति

2368# श्री महेंद्र भट्टः

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उच्च-सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल के विकास में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की प्रगति क्या है;

(ख) भूमि और शहरी नियोजन के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) क्या सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित भू-स्थानिक आंकड़ों तक खुले अभिगम (ओपन एक्सेस) की व्यवस्था की गई है और यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कुशल मानव संसाधन विकसित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): बजट घोषणा के अनुरूप, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन प्रस्ताव के मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं शुरू की गईं। इस संबंध में, प्रस्ताव मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग के साथ व्यापक हितधारक परामर्श किया गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में प्राप्त सुझावों को शामिल करने के बाद, मंत्रिमंडल नोट के रूप में मिशन दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनुमोदन के बाद, मिशन के लिए निर्धारित निधि का उपयोग तदनुसार किया जाएगा।

(ग) दिनांक 15.02.2021 के भू-स्थानिक दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक निधियों का उपयोग करके उत्पन्न किया गया सभी भू-स्थानिक डेटा, सुरक्षा/कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एकत्रित गोपनीय भू-स्थानिक डेटा को छोड़कर, सभी भारतीय संस्थाओं को वैज्ञानिक, आर्थिक और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए आसानी से सुलभ कराया जाएगा और उनके उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तदनुसार, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सृजित सभी भू-स्थानिक डेटा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऑनलाइन मानचित्र पोर्टल https://onlinemaps.surveyofindia.gov.in/ के माध्यम से आसानी से और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय भू-सूचना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईजीएसटी) के माध्यम से, भारतीय सर्वेक्षण विभाग/केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए भूमिति विज्ञान, जीएनएसएस प्रसंस्करण, डिजिटल मानचित्रण और जीआईएस प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी तिरुपति आदि जैसे प्रमुख भारतीय संस्थानों के सहयोग से भी आयोजित किए जा रहे हैं। यूएन-जीजीसीई और यूएन-जीजीआईएम सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भू-स्थानिक प्लेटफार्मों के माध्यम से सक्रिय सहभागिता की जा रही है, ताकि घरेलू क्षमताओं को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

*****